

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
27.11.2019 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 1578 का उत्तर

मिज़ोरम में ब्रॉड गेज़ पटरियां

1578. डॉ. राजदीप राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सिलचर से सैरंग (मिज़ोरम) के बीच ब्रॉड गेज़ (बीजी) पटरियां बिछाने का कार्य निर्धारित समय से बहुत अधिक पीछे है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को पूरा करने की वास्तविक तिथि क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

मिज़ोरम में ब्रॉड गेज़ पटरियों के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में डॉ. राजदीप राय के अतारांकित प्रश्न संख्या 1578 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): सिलचर से सायरंग बड़ी आमान लाइन में 3 परियोजनाएं शामिल हैं इस परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) सिलचर-कैथल खण्ड (19.71 किमी) मुख्य आमान परिवर्तन [लमडिंग - बदरपुर - कटाखाल - सिलचर (210 किमी), बदरपुर - कुमारघाट (118 किमी), अरुणाचल - जिरीबाम (50 किमी) और बरैग्राम - दुलाबछेरा (29.40), करीमगंज - मैशासन (10 किमी) और करीमगंज बाईपास लाइन (3.50 किमी) के आमान परिवर्तन के लिए वस्तुपरक आशोधन] का एक भाग है।

लमडिंग-बदरपुर-कटाखाल-सिलचर खंड का आमान परिवर्तन नवम्बर, 2015 में शुरू किया गया था और संपूर्ण परियोजना नवम्बर, 2017 में चालू की गई थी।

(ii) कटाखाल-भैराबी आमान परिवर्तन परियोजना (84 किमी) मई, 2017 में चालू किया गया था।

(iii) भैराबी-सायरंग नई लाइन (51.38 किमी): परियोजना 2008-09 में स्वीकृत की गई थी। परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 5021 करोड़ रु. है। मार्च, 2019 तक 2672 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। 2019-20 के लिए 750 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है। पूरी परियोजना पर निर्माण संबंधी कार्य शुरू हो गया है।

(ख): भैराबी-सायरंग नई लाइन परियोजना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है औ यह एक घाट खंड है जिसमें सुरंग और उंचे पुलो (70 मीटर से अधिक उंचे) का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त, निर्माण सामग्री (अर्थात बालू, स्टोन, चिप्स इत्यादि) का आभाव है जिसका आसाम से परिवहन किया जाता है। इसके अलावा, सायरंग रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल स्टेशन सुविधाओं के निर्माण के लिए मिजोरम सरकार द्वारा लगभग 54 हेक्टेयर भूमि अभी अधिगृहीत की जानी है।

\*\*\*\*\*